

ई सप्तर

30 अप्रैल 2026 | अंक 203

सात दिन-सात पृष्ठ



- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना कृषि विकास का मॉडल, क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिये रोडमैप तैयार करने में सहायक
- मुख्यमंत्री ने 'रश्मिरेथी पर्व' के मंच से राष्ट्रकवि दिनकर के आदर्शों पर समरस समाज के निर्माण का किया आह्वान
- उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ 60 हजार आरक्षियों का ऐतिहासिक दीक्षान्त समारोह, मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली
- औद्योगिक विकास की 'स्पीड' और निवेश की 'सेफ्टी' से उत्तर प्रदेश बना फार्मा एवं हेल्थकेयर सेक्टर का वैश्विक केंद्र
- यूपी पुलिस की संचार यूनिट हुई और अधिक सशक्त, मुख्यमंत्री ने 936 नवचयनित कर्मियों को सौंपे नियुक्ति-पत्र
- नारी शक्ति के वंदन से सशक्त हुआ काशी का विकास प्रधानमंत्री जी ने 6,330 करोड़ की परियोजनाओं से दी नए भारत की गारंटी
- प्रगति पथ पर दौड़ा नया उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 36,230 करोड़ के 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का ऐतिहासिक लोकार्पण
- गंगा एक्सप्रेस-वे, सिर्फ सड़क नहीं उत्तर प्रदेश की समृद्धि का मार्ग

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना कृषि विकास का मॉडल, क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिये रोडमैप तैयार करने में सहायक



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 अप्रैल, 2026 को यहां लखनऊ में कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन को गति प्रदान कर अन्नदाता किसान की आय में वृद्धि हेतु 09 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषक उत्पादक संगठन एवं प्रगतिशील किसानों के महासंगम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्पष्ट किया कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों के एग्रोक्लाइमेटिक जोन व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिये लक्ष्य तय करना अत्यन्त आवश्यक रहा। इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिये व्यापक रोडमैप तैयार करने में सहायता मिली। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 'विकसित कृषि अभियान' और 'खेती की बात खेत में' कार्यक्रम के दौरान किसानों को पहली बार इनोवेशन को व्यावहारिक धरातल पर उतारने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ और लैब को लैण्ड तक पहुँचाने का अभिनव प्रयास सफल रहा। शासन की योजनाओं के बारे में अन्नदाता किसानों को अवगत कराने के बेहतर परिणाम सामने आए।

प्रदेश सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 69 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित रहे, जिनकी संख्या

बढ़कर 89 हो गई। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में इनोवेशन के साथ-साथ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करते रहे। खेतों में डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। इसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 08 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पहुंच गई। कृषि और मैनुफैक्चरिंग के समन्वय पर जोर देते हुए सरकार ने वैल्यू एडिशन की पहल को भी मजबूती से आगे बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने तकनीक को निर्णायक बताते हुए वाराणसी के इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट और आगरा के लिए स्वीकृत इण्टरनेशनल पोटैटो सेण्टर का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उन्नत बीजों और तकनीक के प्रयोग से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 100 कुन्तल तक पहुंच गया। लागत को कम कर उत्पादन बढ़ाने और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी प्रगतिशील किसानों ने बेहतरीन कार्य किया। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खेतों में 10 से 12 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने और समय पर सीड देने के परिणामस्वरूप कई लाख हेक्टेयर भूमि पर किसानों ने तीन-तीन फसलें लेना प्रारम्भ किया, जिससे उनकी आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई।

विभिन्न जनपदों का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मक्का जैसी फसलों से किसानों ने

प्रति एकड़ भारी मुनाफा कमाया। प्रोक्योरमेण्ट सेण्टर स्थापित होने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम भी मिला। उत्तर प्रदेश 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 211 लाख मीट्रिक टन धान और 245 लाख मीट्रिक टन आलू के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ दलहन, तिलहन, सब्जी, बाजरा आदि के उत्पादन में भी ऊंची छलांग लगा चुका है। इंटरनेशनल पोटैटो सेण्टर की स्थापना से सेंट्रल यूपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की शुरुआत हुई, जिससे किसानों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतरीन दाम मिलना सुनिश्चित हुआ।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा और यह राज्य अनेक क्षेत्रों में देश में नम्बर वन बना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की माटी, जलवायु और मेहनती किसान इस राज्य की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रत्येक राज्य का कृषि रोड मैप बनाने और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए फार्मर आईडी बनाने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर व भागीरथ चौधरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह एवं कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह ओलख सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने 'रश्मि रथी पर्व' के मंच से राष्ट्रकवि दिनकर के आदर्शों पर समस्त समाज के निर्माण का किया आह्वान

24 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कालजयी कृति 'रश्मि रथी' के हीरक जयन्ती वर्ष एवं उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर तीन दिवसीय 'रश्मि रथी पर्व' के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित किया। समतामूलक व सांस्कृतिक समाज के निर्माण हेतु आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने स्मारिका 'रश्मि रथी से संवाद' का विमोचन कर राष्ट्रकवि के सुपौत्र रित्विक उदयन को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 'रश्मि रथी' पर आधारित नाट्य मंचन का अवलोकन किया और कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रकवि दिनकर को साहित्य का शलाका पुरुष बताया, जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का भाव निरंतर परिलक्षित होता रहा। उन्होंने 'रश्मि रथी' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' की पंक्तियों का स्मरण कर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि भारत की स्वाधीनता को सुरक्षित रखकर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो समाज को जातिवाद से पूरी तरह मुक्त रहना होगा। राष्ट्रकवि ने अपनी लेखनी से देश व समाज की चेतना को जागृत कर एकजुटता का मजबूत संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिनकर की पंक्तियों से प्रेरित करते हुए विघ्नों में राह बनाने वाले को ही सच्चा सूरमा बताया। उन्होंने 'रश्मि रथी' के नायक कर्ण की गाथा को वर्तमान पीढ़ी के लिए नयी प्रेरणा बताते हुए इसके अधिकाधिक मंचन पर बल दिया। पर्व की आगामी रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे दिन वैदिक परम्परा को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकानन्द और तीसरे दिन 26 अप्रैल को स्वराज्य का ऐतिहासिक उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर आधारित नाट्य मंचन सुनिश्चित हुआ।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि बताते हुए जानकारी दी कि कार्यक्रम के अंतिम दिन अटल जी की कविताओं पर आधारित नृत्य-नाटिका 'अटल स्वरांजलि' का आयोजन भी निर्धारित हुआ, जिससे युवा पीढ़ी साहित्य के माध्यम से समाज



और राष्ट्र की दिशा को भली-भांति समझ सके। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारत की महान संस्कृति के प्रदर्शन को सराहनीय बताते हुए कहा कि 'रश्मि रथी' और गीता का उपदेश विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने नई लकीर खींचने का सशक्त सन्देश बना।

24 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कालजयी कृति 'रश्मि रथी' के हीरक जयन्ती वर्ष एवं उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर तीन दिवसीय 'रश्मि रथी पर्व' के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित किया। समतामूलक व सांस्कृतिक समाज के निर्माण हेतु आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने स्मारिका 'रश्मि रथी से संवाद' का विमोचन कर राष्ट्रकवि के सुपौत्र रित्विक उदयन को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 'रश्मि रथी' पर आधारित नाट्य मंचन का अवलोकन किया और कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रकवि दिनकर को साहित्य का शलाका पुरुष बताया, जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का भाव निरंतर परिलक्षित होता रहा। उन्होंने 'रश्मि रथी' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' की पंक्तियों का स्मरण कर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि भारत की स्वाधीनता को सुरक्षित रखकर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना

को साकार करना है, तो समाज को जातिवाद से पूरी तरह मुक्त रहना होगा। राष्ट्रकवि ने अपनी लेखनी से देश व समाज की चेतना को जागृत कर एकजुटता का मजबूत संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिनकर की पंक्तियों से प्रेरित करते हुए विघ्नों में राह बनाने वाले को ही सच्चा सूरमा बताया। उन्होंने 'रश्मि रथी' के नायक कर्ण की गाथा को वर्तमान पीढ़ी के लिए नयी प्रेरणा बताते हुए इसके अधिकाधिक मंचन पर बल दिया। पर्व की आगामी रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे दिन वैदिक परम्परा को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकानन्द और तीसरे दिन 26 अप्रैल को स्वराज्य का ऐतिहासिक उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर आधारित नाट्य मंचन सुनिश्चित हुआ।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि बताते हुए जानकारी दी कि कार्यक्रम के अंतिम दिन अटल जी की कविताओं पर आधारित नृत्य-नाटिका 'अटल स्वरांजलि' का आयोजन भी निर्धारित हुआ, जिससे युवा पीढ़ी साहित्य के माध्यम से समाज और राष्ट्र की दिशा को भली-भांति समझ सके। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारत की महान संस्कृति के प्रदर्शन को सराहनीय बताते हुए कहा कि 'रश्मि रथी' और गीता का उपदेश विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने नई लकीर खींचने का सशक्त सन्देश बना। उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ 60

उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ 60 हजार आरक्षियों का ऐतिहासिक दीक्षान्त समारोह, मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली



26 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती वर्ष 2025-26 बैच के दीक्षान्त परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर भव्य परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण पूरा करने वाली बेटियों के शौर्य की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों का आह्वान करते हुए उन्हें अपराधियों के प्रति कठोर और नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने का मूल मंत्र दिया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनि्युक्त पुलिस कार्मिक पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परम्परा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए और बताया कि इन बेटियों ने अपनी व्यावसायिक क्षमता से पुलिस बल को विश्व स्तरीय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दीक्षान्त परेड का आयोजन

प्रदेश के 112 रिक्रूट ट्रेनिंग केन्द्रों पर एक साथ भव्य रूप में सम्पन्न हुआ।

पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण का पसीना रणभूमि में रक्त बहने से रोकता है। उन्होंने पूर्व की मात्र 3,000 की प्रशिक्षण क्षमता को रिकॉर्ड समय में बढ़ाकर 60,244 तक पहुँचाने को विगत 09 वर्षों की प्रगति का जीवंत प्रमाण बताया। प्रदेश के 55 जनपदों में पुलिस कार्मिकों के लिए हाई राइज आवासीय सुविधाओं और 'यू0पी0 पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल' जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों की शुरुआत हुई। पुलिस बल को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने हेतु इन्सास और एस0एल0आर0 राइफलों से प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 'मिशन कर्मयोगी' के विशेष मॉड्यूल लागू किए गए। मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ साझा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब देश की स्मार्ट पुलिस के रूप में स्थापित हुई, जहाँ अब दंगे और माफिया राज का कोई स्थान

नहीं बचा। अपराधियों के मन में व्याप्त भय और कानून के राज ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और आर्थिक प्रगति के द्वार खोले।

मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा और स्वावलम्बन हेतु पिंक पुलिस बूथों तथा तीन नई महिला पी0ए0सी0 बटालियनों के गठन की प्रक्रिया को ऐतिहासिक कदम बताया। पुलिस बल में बेटियों की 20 प्रतिशत अनिवार्य भागीदारी और महिला कार्यबल का 36 प्रतिशत से अधिक होना प्रदेश की बदली हुई कार्यसंस्कृति को दर्शाता है। पुलिस के रिस्पांस टाइम में भारी कमी और हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की स्थापना ने जाँच प्रणाली को वैज्ञानिक और त्वरित बनाया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने भी मुख्यमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पारदर्शी भर्ती और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अर्जित की गई अभूतपूर्व उपलब्धियों को रेखांकित किया।

औद्योगिक विकास की 'स्पीड' और निवेश की 'सेफ्टी' से उत्तर प्रदेश बना फार्मा एवं हेल्थकेयर सेक्टर का वैश्विक केंद्र



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अप्रैल को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के प्रावधानों के अंतर्गत 17 फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) प्रदान किया। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव-2026 के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को सफल निवेश की शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर को प्रदेश के औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अब 'सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड' की गारंटी बन चुका है और इसकी पहचान अब भरोसेमंद तथा समयबद्ध आपूर्ति (ट्रस्ट और टाइमली डिलीवरी) के रूप में स्थापित हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि नए भारत में देश की अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को छुआ और भारत वर्तमान में विश्व के 200 देशों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में हुआ यह निवेश केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास से जुड़ा रहा। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में होने वाला लगभग 2,000 करोड़ रुपये का यह निवेश प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले

जाने में सहायक सिद्ध हुआ, जिससे 10 हजार से अधिक स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नीयत के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में विकसित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की जीएसडीपी बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश के पास एक विशाल बाजार, उद्योगों के अनुकूल माहौल और पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध रहा, साथ ही यहां का 56 फीसदी युवा वर्कफोर्स स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होकर बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहा। कानून व्यवस्था को विकास की पहली शर्त बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश ने 'पॉलिसी पैरालिसिस' के दौर को पीछे छोड़कर 'पॉलिसी स्टेबिलिटी' को अपनाया, जहां वर्तमान में 34 से अधिक सेक्टरल पॉलिसी और निवेश मित्र, निवेश सारथी व उद्यमी मित्र जैसे माध्यम उद्यमियों को अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2017 में कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर अब 32 हजार हो गई और राज्य को प्राप्त 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतरे, जबकि 07 से 08 लाख करोड़ रुपये के नए प्रस्तावों को शीघ्र क्रियान्वित करने की

दिशा में कार्य बढ़ा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या 40 से बढ़ाकर 83 की और ललितपुर में 1,500 एकड़ में फार्मा पार्क तथा गौतमबुद्धनगर में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया, उनमें बायोजेंटा लाइफसाइंस (1,250 करोड़ रुपये), रोमन्स मेडवर्ल्ड (136.89 करोड़ रुपये), हाईग्लॉस लेबोरेट्रीज (120 करोड़ रुपये), कोटेक हेल्थकेयर (100 करोड़ रुपये), जेबी रेमेडीज (70 करोड़ रुपये), पॉजिट्रॉन बायोजेनिक्स (60.24 करोड़ रुपये), आईवी टेकहेल्थकेयर (56.12 करोड़ रुपये), जेबीजेएम पैरेंट्रल्स (51 करोड़ रुपये), रास्पा फार्मा (45.21 करोड़ रुपये), एनबीएस ग्रुप (42.59 करोड़ रुपये), वेलनेस जेडक्योर फार्मास्युटिकल्स (11.65 करोड़ रुपये), कैमले इण्डस्ट्रीज (10 करोड़ रुपये), रेडिकॉन लैबोरेट्रीज (10 करोड़ रुपये), संजीवनी मेडिटेक (7.95 करोड़ रुपये), सेफकॉन लाइफ साइंसेज (6.43 करोड़ रुपये), आरएपी मेड सर्जिकल (5.53 करोड़ रुपये) और वोडा केमिकल (4.84 करोड़ रुपये) शामिल रहीं। निवेशकों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अटूट विश्वास प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी प्रगति का आधार बनाने का संकल्प दोहराया।

यूपी पुलिस की संचार यूनिट हुई और अधिक सशक्त, मुख्यमंत्री ने 936 नवचयनित कर्मियों को सौंपे नियुक्ति-पत्र



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 28 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस दूरसंचार विभाग के 936 नवचयनित प्रधान परिचालकों और प्रधान परिचालकों (यांत्रिक) को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि कम्युनिकेशन किसी भी व्यवस्था का एक अत्यंत सशक्त माध्यम बना। कम्युनिकेशन के सशक्त होने से पुलिस और अन्य फोर्सेज सटीक कार्रवाई करने तथा आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने में सफल हुई। इन नए प्रधान परिचालकों के चयन से संचार यूनिट को और अधिक मजबूती मिली। नवचयनित अभ्यर्थियों को आठ माह के प्रशिक्षण के दौरान सामान्य वॉकी-टॉकी से लेकर पुलिस दूरसंचार की नई प्रगति और स्मार्ट पुलिसिंग में दूरसंचार की प्रभावी भूमिका को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अभ्यर्थियों की योग्यता व क्षमता के आधार पर संपन्न हुई। कई अभ्यर्थियों ने अपने और अपने परिवार की इस आकांक्षा को साझा किया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रहे, जिसे सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया। मुख्यमंत्री ने नवचयनित कर्मियों का आह्वान किया कि जिस ईमानदारी और निष्पक्षता से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की, उसी लगन से वे भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहकर ही वे देश और समाज को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं

देने में सक्षम बनेंगे। इन कर्मियों को दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का हिस्सा बनकर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की सेवा करने का सुअवसर मिला। उन्होंने स्मरण कराया कि परसों ही 60,244 पुलिस आरक्षियों की दीक्षांत परेड प्रदेश के 112 केंद्रों पर भव्यता के साथ संपन्न हुई। विगत नौ वर्षों में राज्य में 2 लाख 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की गई।

पूर्व की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नौ वर्ष पूर्व निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया लगभग असंभव मानी गई और वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में मात्र 3,000 पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता उपलब्ध रही। इसके विपरीत, वर्ष 2025 में 60,244 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण प्रदेश के ही केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साफ नीयत और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर यह सकारात्मक परिणाम सामने आया। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस वर्ष होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई सहित लगभग एक लाख नई भर्तियों का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इसके अलावा, विगत तीन दिनों में 40,000 से अधिक होमगार्ड कर्मियों के लिए भर्ती परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

उत्तर प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बताया गया जिसने 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप यूपी पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए ढेरों मेडल जीते। पुलिस अवस्थापना

सुविधाओं में हुए ऐतिहासिक सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में 10 जनपदों में पुलिस लाइन तक उपलब्ध नहीं रही और सामान्य सुविधाओं का घोर अभाव रहा। इस कमी को दूर करते हुए 55 जनपदों में खपरैल बैरकों के स्थान पर हाईराइज बिल्डिंग में आधुनिक बैरक की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में मॉडल थानों और नए फायर स्टेशनों का निर्माण हुआ तथा एसएसएफ व एसडीआरएफ का गठन किया गया। वीरांगनाओं के सम्मान में पीएसी की तीन नई महिला पुलिस बटालियन भी स्थापित की गईं।

तीन नए आपराधिक कानूनों के वर्ष 2024 में लागू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने इसकी पूर्ण तैयारी पहले ही पूर्ण कर ली। सात वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की अनिवार्यता के दृष्टिगत स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ने सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई और प्रत्येक जनपद में दो-दो मोबाइल फॉरेंसिक लैब ने पूरी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दीं। प्रदेश में 'ए' ग्रेड की 12 एफएसएल यूनिट संचालित हुईं और 6 के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि दंगा मुक्त और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानून का राज स्थापित होने से बड़े निवेशक राज्य में आए। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, डबल इंजन की सरकार के शुद्ध नीयत से किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया।

नारी शक्ति के वंदन से सशक्त हुआ काशी का विकास प्रधानमंत्री जी ने 6,330 करोड़ की परियोजनाओं से दी नए भारत की गारंटी



वाराणसी में 28 अप्रैल 2026 को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ग्राउंड में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के वंदन और विकास का ऐतिहासिक उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने 6,330 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 163 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सांसद नितिन नबीन जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति का अभिवादन करते हुए बनास डेयरी के 3,21,813 दुग्ध उत्पादकों को 105 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस हस्तांतरित किया और काशी से पुणे तथा अयोध्या से मुंबई के बीच दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं के बैठने के लिए बनाए गए सेक्टर में जाकर प्रधानमंत्री जी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और विभिन्न वर्गों की नारी शक्ति ने उन्हें प्रतीक चिह्न भेंट किए। कार्यक्रम में रेलवे और विकास परियोजनाओं सहित सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

काशी को माता श्रृंगार गौरी, अन्नपूर्णा और गंगा जैसी दिव्य शक्तियों की भूमि बताते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत

का सबसे मजबूत स्तंभ देश की नारी शक्ति ही है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि नीति निर्माण में बहनों और बेटियों की भूमिका बढ़ाना देश की आवश्यकता बन गया। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बावजूद परिवारवादी विपक्षी दलों के विरोध के कारण संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया, जिससे महिलाओं के अधिकार रुके रहे।

प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ता से कहा कि महिला आरक्षण लागू कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक महिला के सशक्त होने से पूरा परिवार, समाज और देश मजबूत होता है और इसी ध्येय के साथ सरकार की नीतियों में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ शौचालय निर्माण, 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा योजना जैसे कदमों का उल्लेख किया जिससे महिलाओं की पढ़ाई, कमाई और दवाई सुनिश्चित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होने से उन्हें संपत्ति की मालकिन बनने का अधिकार मिला।

उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के बदलते हालात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ने बहनों को सुरक्षा का नया भरोसा दिया और महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों

में तेजी से फैसले आने लगे। आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि देश की लगभग 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं और तीन करोड़ बहनें 'लखपति दीदी' बनीं। कृषि सखियों, 'नमो ड्रोन दीदी' और रक्षा क्षेत्रों में बेटियों के प्रवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मूल मंत्र 'नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान और नारी का जीवन आसान' ही रहा। काशी के संवेदनशील विकास की चर्चा करते हुए 500 बेड के मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक, गंगा नदी पर सिग्रेचर ब्रिज और संत कबीर स्थली के विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके विजन का ही परिणाम रहा कि पूरा देश नए भारत का दर्शन कर रहा है, जो भौतिक विकास के साथ-साथ विरासत को भी सहेज कर आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जी ने नारी, गरीब, युवा और अन्नदाता किसान को केंद्र में रखकर समग्र समाज का विकास सुनिश्चित किया। काशी को विगत 12 वर्षों में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतरीं और वर्तमान में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रगति पर रहे। सांसद नितिन नबीन जी ने भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधी आबादी के जीवन में आए व्यापक बदलावों की सराहना की।

प्रगति पथ पर दौड़ा नया उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया 36,230 करोड़ के 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का ऐतिहासिक लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 29 अप्रैल, 2026 को जनपद हरदोई में 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ-प्रयागराज) का भव्य लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री जी ने नृसिंह भगवान की भूमि को नमन करते हुए इस सम्पूर्ण क्षेत्र को किसी तीर्थ के समान बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे को माँ गंगा का आशीर्वाद निरूपित करते हुए कहा कि अब श्रद्धालुओं का कुछ ही घण्टों में संगम पहुंचना तथा काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन कर वापस आना सम्भव हो गया। जिस प्रकार माँ गंगा हजारों वर्षों से देश व प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं, उसी प्रकार आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफ-लाइन बनने जा रहा है।

इस एक्सप्रेस-वे को प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के साथ ही एनसीआर की सम्भावनाओं को समीप लाने वाला माध्यम बताया गया। इसके किनारे नये औद्योगिक अवसर विकसित करने हेतु हरदोई के साथ ही अन्य जनपदों में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, उन्नाव व शाहजहांपुर सहित सभी 12 जनपदों में नये उद्योग स्थापित होने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसे केवल हाई स्पीड सड़क न मानकर नई सम्भावनाओं और नये अवसरों का गेट-वे बताया गया। 600 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस-वे से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आना तय माना गया, जिससे बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित हुई।

देश के तीव्र विकास के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक बताते हुए प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में दिसम्बर 2021 में हुए इसके शिलान्यास का स्मरण कराया। पांच वर्ष से कम समय में उत्तर प्रदेश का यह सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो



गया। इसके निर्माण पूरे होने के साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसके तहत इसे मेरठ से आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक पहुंचाने तथा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ने की योजना बनी। इसे डबल इंजन सरकार का विजन बताया गया। प्रधानमंत्री जी ने विगत चार-पांच दिनों से माँ गंगा के सान्निध्य में रहने को अद्भुत संयोग बताया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस एक्सप्रेस-वे का नाम माँ गंगा के नाम पर रखने पर भारी प्रसन्नता व्यक्त की।

युवाओं द्वारा 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' और ओडीओपी जैसी योजनाओं की ताकत से नये कीर्तिमान गढ़ने का उल्लेख करते हुए बताया गया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से छोटे उद्योगों तथा एमएसएमई को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। मेरठ के स्पोर्ट्स के सामान से लेकर प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद तक बड़े पैमाने पर देश-दुनिया के बाजारों तक पहुंचने का मार्ग सुलभ हुआ। पूर्व में बीमारू राज्य कहलाने वाले उत्तर प्रदेश को अब वन ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर बताया गया। प्रदेश को मैनुफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लगातार हुए कार्यों का उल्लेख हुआ, जिससे प्रदेश की पहचान पलायन की जगह इन्वेस्टर्स समिट और इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से बन गई। भारत को दुनिया का बड़ा मोबाइल निर्माता बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा। साथ ही, डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के निर्माण से प्रदेश की सामरिक ताकत में भी जबरदस्त वृद्धि हुई।

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसके विरोधी दलों के कारण पारित न हो पाने पर खेद व्यक्त किया, जिसके लागू होने पर महिलाओं को संसद व विधान सभाओं में 2029 से ही आरक्षण मिल जाता। दुनिया के बड़े देशों की अस्थिर हालत के बीच भारत के विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने का विशेष उल्लेख किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि उनके कर-कमलों से उनकी विराट सोच के अनुरूप गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाता किसानों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 594 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस-वे के लिए 18 हजार एकड़ भूमि सहर्ष उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेस-वे से आच्छादित जनपदों में इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल क्लस्टर एण्ड लॉजिस्टिक हब विकसित करने की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ी। वर्ष 2017 से पूर्व की अराजकता पूर्ण स्थिति की तुलना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विगत 09 वर्षों में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, हाई-वे और चार लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का बेहतरीन नेटवर्क खड़ा हुआ। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मोर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक एवं विशाल जनसमूह उपस्थित रहे।

गंगा एक्सप्रेस-वे

सिर्फ सड़क नहीं उत्तर प्रदेश की समृद्धि का मार्ग



सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए
निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएस द्वारा प्रकाशित